EDII

Rajasthan Patrika

August 01, 2019
Page No. 03

नई औद्योगिक नीति के निर्माण के लिए...

सीएम ने किया 10 टास्क फोर्स का गठन

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय टास्क फोर्स समिति

अहमदाबाद. मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने औद्योगिक क्षेत्र में विकास की तेज रफ्तार से वैश्विक औद्योगिक गंतव्य बन रहे गुजरात की नई औद्योगिक नीति को समयानुकूल जरूरतों के अनुसार तैयार करने के सुझाव, समीक्षा और अध्ययन के लिए 10 विभिन्न टास्क फोर्स समितियों के गठन का निर्णय किया है।

उल्लेखनीय है कि पहली जनवरी 2015 से लागू राज्य की वर्तमान औद्योगिक नीति की अवधि इस वर्ष दिसम्बर में पूरी हो रही है।

मुख्यमंत्री ने इस संदर्भ में आने वाले समय के उद्योगों और उसके अनुषांगिक मामलों के सर्वग्राही अध्ययन और समीक्षा कर उसके अनुरूप नई उद्योग नीति तैयार करने का औद्योगिक अनुकूल दृष्टिकोण अपनाया है।

इस उद्देश्य के लिए उन्होंने 10 टास्क फोर्स समितियों के गठन को स्वीकृति प्रदान की है। प्रस्ताव के मुताबिक ये सभी टास्क फोर्स समितियां समय-समय पर बैठक आयोजित कर तीन महीने में राज्य के उद्योग आयुक्त को अपनी सिफारिशें सौंपेंगी। राज्य स्तर की टास्क फोर्स समिति मुख्य सचिव डॉ. जे एन सिंह की अध्यक्षता में गठित की गई है। इस समिति में वित्त, वन एवं पर्यावरण तथा राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिवों के अलावा उद्योग विभाग के प्रधान सचिव, वाणिज्य कर आयुक्त, उद्योग आयुक्त, उद्योग विभाग के संयुक्त सचिव, उप सचिव और विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) का समावेश किया गया है।

इस टास्क फोर्स के अन्य गैर सरकारी सदस्यों के रूप में गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, भारतीय उद्योग परिसंघ (तथा उद्योग संगठन-एसोचैम की गुजरात इकाई के अध्यक्ष, पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी के निदेशक सी. गोपालकृष्णन, भारतीय प्रबंध संस्थान-अहमदाबाद (आईआईएम-ए) के प्रोफेसर सेबेस्टियन मॉरिस, भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान के प्रोफेसर दिनेश अचर्या औक किरण जोषी रहेंगे। वहीं, अतिरिक्त उद्योग आयुक्त इस समिति के सदस्य सचिव होंगे।

राज्य स्तर की इस टास्क फोर्स समिति के अलावा उद्योग आयुक्त की अध्यक्षता में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (एमएसएमई) क्षेत्र के विकास, थ्रस्ट सेक्टर और बड़े उद्योगों के विकास, बीमार इकाईयों की पुनर्स्थापना के लिए तथा स्टार्टअप एवं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए समितियां गठित की गई हैं।

प्रस्तावित नई औद्योगिक नीति के तहत पर्यावरणीय सुरक्षा एवं औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण के लिए वन एवं पर्यावरण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, औद्योगिक आधारभूत सुविधा विकास और जमीन संबंधित मामलों के लिए गुजरात औद्योगिक विकास निगम के प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में, व्यापार, वाणिज्य एवं सेवा क्षेत्र के विकास के लिए विशेष आयुक्त कॉमर्शियल टैक्स की अध्यक्षता में और कौशल उन्नयन तथा उद्योगों के अनुरूप रोजगार निर्माण के लिए रोजगार तालीम के निदेशक की अध्यक्षता में टास्क फोर्स गठित की गई है।

इन सभी टास्क फोर्स में उद्योग-व्यापार जगत, युवा स्टार्टअप तथा संबंधित विषयों के विशेषज्ञों की सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए उस क्षेत्र के अग्रणियों की भी गैर सरकारी सदस्य के रूप में नियुक्ति की गई है। मुख्यमंत्री ने इस प्रस्तावित नई औद्योगिक नीति में हितधारकों के विचार, अनुभव और सुझाव हासिल करने के लिए प्रो-पीपुल, प्रो-एक्टिव और पारदर्शी सुशासन के भाव से इन सभी समितियों के गठन की अभिनव पहल की है।